Gmail

Mahesh Pratap Singh <yogimpsingh@gmail.com>

20-01-2026

Mahesh Pratap Singh <yogimpsingh@gmail.com> 19 January 2026 at 22:23
To: SHAKUNTALA GAUTAM <hearingcourts9.upic@up.gov.in>
Cc: registrarmgkvp <registrarmgkvp@gmail.com>

BEFORE THE HON'BLE STATE INFORMATION COMMISSION, UTTAR PRADESH Appeal No: S09/A/1994/2025 (**Registration No:** A-20250801784)

Yogi M. P. Singh ... *Appellant* **Vs. Public Information Officer, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith (MGKVP)** ... *Respondent*

WRITTEN SUBMISSION ON BEHALF OF THE APPELLANT

Most Respectfully Showeth:

1. **Non-Compliance of Order dated 28.11.2025:** The Hon'ble Commission, in its order dated November 28, 2025, explicitly noted that the information previously provided by the PIO was "not clear or point-wise". The Respondent was directed to provide "clear, point-wise, and amended information" to the Appellant before the next hearing.

2. **Continued Obstruction of Information:** As of today, the Respondent has failed to provide the specific data requested in the original RTI application regarding affiliation details (2010–2025) and the affiliation mechanism. The PIO continues to rely on generic website links, which the Commission has already deemed unsatisfactory.

3. **Deliberate Misleading:** The Respondent's actions constitute a "malafide" denial of information. By providing cryptic responses, the PIO is shielding the administrative processes of the university from public scrutiny, thereby undermining the spirit of the RTI Act, 2005.

4. **Violation of RTI Standards:** Directing an applicant to a generic home page (www.mgkvp.ac.in) without specific URLs for the requested lists of affiliated institutions is a violation of Section 6(1) of the RTI Act.

PRAYER

In light of the persistent non-compliance and the "Jungle Raj" functioning of the concerned office, the Appellant humbly prays that this Hon'ble Commission may be pleased to:

- **Impose Penalty:** Invoke **Section 20(1)** of the RTI Act, 2005, and impose a penalty of ₹250 per day (up to ₹25,000) on the PIO, Dr. Sunita Pandey, for deliberate delay and providing misleading information.

- **Disciplinary Action:** Recommend disciplinary action against the First Appellate Authority (FAA) under **Section 20(2)** for failing to perform their quasi-judicial duty.

- **Mandatory Disclosure:** Direct the Respondent to provide the information in a hard copy or specific PDF format, point-by-point, as originally requested.

Date: 20/01/2026 **Place:** Lucknow / Mirzapur

Respectfully Submitted,

Yogi M. P. Singh Appellant Mobile: 7379105911

[Quoted text hidden]

ORDERS9.pdf
92K

समक्ष—शकुन्तला गौतम, राज्य सूचना आयुक्त उ0प्र0, सुनवाई कक्ष एस—9

अपील संख्या एस 09/ए/1994/2025

श्री योगी एमपी सिंह **बनाम** ज0सू0अ0 कार्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनपद—वाराणसी

आदेश

कम्प्लेन्ट व अपील ट्रैकिंग सिस्टम (CATS) के माध्यम से पंजीकृत की गयी अपील आज सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गयी। दिनांक—28.11.2025 की सुनवाई हेतु अपीलार्थी को ई—मेल से दिनांक—17.11.2025 को नोटिस प्रेषित की गयी तथा वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुनवाई हेतु लिंक प्रेषित किया गया। पुकार करायी गयी। अपीलार्थी अनुपस्थित है। विपक्षी जनसूचना अधिकारी डॉ0 सुनीता पाण्डेय, कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनपद—वाराणसी ऑनलाइन उपस्थित हुयी।

विपक्षी जनसूचना अधिकारी का आयोग को सम्बोधित लिखित अभिकथन दिनांक—06.11.2025 ई—मेल से प्रेषित किया गया है, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना पोर्टल के माध्यम से पत्र दिनांक—10.06.2025 के द्वारा दी जा चुकी है, परन्तु विपक्षी जनसूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना स्पष्ट बिन्दुवार नहीं है।

उपरोक्त स्थिति में उपस्थित विपक्षी जनसूचना अधिकारी डॉ0 सुनीता पाण्डेय, कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनपद—वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 व उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के नियमों व प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी के आवेदन पत्र के क्रम में सुस्पष्ट व बिन्दुवार संशोधित सूचना नियत तिथि से पूर्व अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए सूचना की प्रति एवं प्रेषण साक्ष्य के साथ लिखित अभिकथन अग्रिम नियत सुनवाई तिथि से पूर्व आयोग को उपलब्ध करायी जाये, अन्यथा की स्थिति में आयोग द्वारा अग्रिम आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अपीलार्थी को इस आशय की नोटिस प्रेषित की जाये कि वह अगली नियत सुनवाई तिथि पर उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के नियम 9(1) के तहत स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक—20.01.2026 को पेश हो।

28.11.2025